Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

डिजिटलीकरण' भारत की चुनौतियां एवं भविष्य

डॉ0 राजन गुप्ता
समाजशास्त्र विभाग
मां गायत्री महाविद्यालय
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश : – ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का स्वप्न गांधी के 'ग्राम स्वराज' से लेकर आधुनिक समय के स्मार्ट विलेज तक की यात्रा तय कर रहा है। लेकिन धरातल पर देखें तो स्थिति जस की तस बनी हुयी है। हालांकि यह दौर संक्रमण का है; और विगत कुछ योजनाओं में निश्चित तौर पर ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा और ग्लोबल विलेज के दायरे में खीचने का कार्य किया है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए गये हैं। इसके अन्तर्गत बैंक–खातों को आधार से जोड़ना, विभिन्न आंकड़ों का डिजिटल रूप में संग्रहण, नोटबंदी के द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना आदि प्रयास शामिल हैं। डिजिटलीकरण के लिये नीतिगत प्रयास करना इस मुद्दे का एक पहलू मात्र है। इन नीतिगत प्रयासों की सफलता इस बात में निहित है कि दूर–दराज के गांवों में निवास करने वाली आजादी के बीच डिजिटल तकनीक की स्वीकार्यता कितनी है, क्योंकि इसके बिना डिजिटल पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले ग्रामीण समुदायों का सशक्तीकरण एक कठिन चुनौती बन जायेगा।

मुख्य शब्द : डिजिटलीकरण, ग्लोबल विलेज, ग्राम स्वराज, सशक्तीकरण आदि।

एक समय था जब भारत में कम्प्यूटर के आगमन और उसकी स्वीकार्यता को आधुनिकीकरण की ओर एक आवश्यक कदम मात्र कहा गया था। परन्तु सच तो यह है कि उत्क्रान्ति का अपना आवेग होता है, तथा इसकी अपनी एक दिशा होती है और किसी देश अथवा समाज की स्वेच्छा, उसकी अपनी सहभागिता को तो प्रभावित कर सकती है, उससे उत्क्रान्ति के नियत भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कुछ विकासक्रम अपरिहार्य होते हैं और वैश्विक डिजिटलीकरण उसका सबसे सशक्त उदाहरण है। तकनीक ने आधुनिक मानव समाज की व्यापक होती मूलभूत आवश्यकताओं और सुखद भविष्य की कल्पनाओं के बीच असीमित अपेक्षाओं के पुल बांध दिए है। तकनीक इक्कीसवी सदी की विकास योजनाओं की धुरी बन बदलाव के बड़े बवंडर परोसने लगी है। लेकिन ग्रामीण भारत के दशकों पुराने बुनियादी प्रश्न मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती इत्यादि अब भी चुनौती बने हुए है।[1]

ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का स्वप्न गांधी के 'ग्राम स्वराज' से लेकर आधुनिक समय के 'स्मार्ट विलेज' तक की यात्रा तय कर रहा है। लेकिन धरातल पर देखें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि यह दौर संक्रमण का है, और विगत कुछ योजनाओं ने निश्चित तौर पर ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा और ग्लोबल विलेज के दायरे में खींचने का कार्य किया है, जिससे भूमिगत भारत अब एक नियत कल की ओर तेजी सु बढ़ने लगा है। भारत सरकार के साथ कई बड़ी कम्पनियों ने भी डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। टाटा ने इस दिशा में प्रगति भी की है।[2] इंटेल ने हाल ही में 'डिजिटल स्किल्स फॉर इंडिया' पहल का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 'डिजिटल कौशल प्रशिक्षण एप्लीकेशन' लाया गया, जो पांच भारतीय भाषाओं में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन, हेल्थकेयर और साफ–सफाई आदि मॉड्यूल के साथ डिजिटल साक्षरता की दिशा में काम करेगा।

ग्रामीण भारत में जाति, संयुक्त परिवार, उत्सव तथा धार्मिक विश्वास आदि महत्व क्षीण होती जा रही है। स्कूल, राजनीतिक दल, सिनेमा, सामुदायिक योजना का असार दूरस्थ गांवों तक बढ़ गया है। जिन परिवर्तनों के बारे में हमें यहां जानकारी मिलती है, वे महत्वपूर्ण मात्रा में हैं।[3]

ग्रामीण भारत में डिजिटलीकरण के समक्ष चुनौतियाँ :

ग्रामीण भारत में डिजिटलीकरण के समक्ष चुनौतियों को अद्योलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, यथा–

- स्तरीय शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करना।
- शिक्षा के ऊपर होने वाले खर्च को नियंत्रित रखना ताकि राजस्व पर संतुलित दबाव हो।
- इंटरनेट पर लिंगानुपात कम करना।
- नारी सशक्तिकरण की दिशा में सूचना और सहभागिता को सहज करना।
- नागरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ढांचे को ई–विस्तार देना।
- जनोपयोगी योजनाओं का पारदर्शिता से क्रियान्वयन के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- रोजगार और जीविका के साधन उपलब्ध करना।
- जीवन–स्तर में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना।
- सृजनशील, कला और संस्कृति की संरक्षण।
- लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करते हुए, सबल व सक्षम नागरिक तैयार करना।
- प्रशासन और नागरिक सेवाओं की आसान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना।
- खेती और किसान को मुख्यधारा से जोड़ना।
- डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक अवसंरचना की अपर्याप्तता, जैसे– बिजली, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधाओं की कमी आदि।

- भुगतान के लिये ग्रामीण आबादी नकद पर जितना विश्वास करती है और उसके इस्तेमाल मं सहज होती है, उतनी सहज यह डिजिटल भुगतान तकनीकों के प्रति नहीं होती। इसके पीछे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी एक कारण है।
- भारत की ग्रामीण आबादी डिजिटल रूप में अशिक्षित है। डिजिटल व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा को पढ़ने, लिखने, समझाने और संप्रेक्षित करने तथा नई तकनीकों के प्रति अज्ञानता डिजिटल ग्रामीण भारत की राह में बाधा है।

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव अपेक्षित है। न केवल नीतिगत–स्तर पर वरन ढांचागत–स्तर पर भी शिक्षा को ज्यादा रोजगार–परक और हुनर–केन्द्रित बनाया जाता है। नई शिक्षा नीति और ई–शिक्षा, दोनों के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक–स्तर पर तकनीक की मदद से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हुए बदलाव निश्चित तौर पर भारत के लिए बेहतर संकेत है। एक लाख करोड़ रुपये के अति महत्वकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत के सभी स्कूलों को वाई–फाई से जोड़कर, वृहदज्ञान तंत्र खड़ा किया जाना है, इसके साथ ही स्तरीय पाठ्यसामग्री ग्रामीण भारत के बच्चों के पास भी सहज उपलब्ध हो सकेंगी।[4]

आज डिजिटल शिक्षा सामग्री का बड़ा भंडार, जन–सहभागिता और सरकारी गैर–सरकारी उद्यमों के सहयोग से संभव हो पाया है। भारत सरकार के साथ कई बड़ी कम्पनियों ने भी डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।

वर्षों तक भारत एक जटिल देश रहा है, जिसके कारण आम आदमी के लिये सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता हासिल करना मुश्किल रहा है। तकनीक हमेशा से शिक्षा के नए युग में प्रवेश का मध्यम रही है, चाहे वह पेपर हो, प्रिटिंग प्रेस हो, ब्लैकबोर्ड हो, पुस्तकें हो अथवा इक्कीसवीं सदी का मोबाइल ब्रॉड्बैंड और इंटरनेट सुविधा हो। शिक्षा में तकनीक की महत्ता मात्र पढ़ने की क्षमता और गणित के ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने और मातृ एवं शिशु मृत्युदर को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हमारा समाज एक अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। जो चुनौतियाँ आज हमारे सामने हैं, उनकी आवृत्ति और प्रबलता में वृद्धि सम्भव है। बढ़ती जनसंख्या और समाप्त प्रायः संसाधनों के साथ हमारे देश को नयी समस्याओं का समाना करना है।

शिक्षा की गुणवत्ता का एक और प्रत्यक्ष लाभ मातृ एवं शिशु मृत्युदर को कम करना रहा है। 1970 के बाद से दुनियाभर में बाल मृत्युदर में आई कमी का प्रमुख कारण महिलाओं में प्रजनन की आयु के समय शिक्षा प्राप्ति में हुई वृद्धि है।[5] शिक्षित महिलाएं स्वयं का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पाती है। इंटरनेट पर अपसी संवाद और समूहों में जुड़ने से स्त्रियों के आत्मविश्वास में वृद्धि देखी गई जिससे घरेलू हिंसा जैसे जटिल मामलों में कमी पायी गई है। लेकिन इंटरनेट पर लिंगानुपात में बढ़ा अंतर चिंता का कारण है। इसे दूर करने के लिए गूगल का एक प्लेटफोर्म खासा मददगार साबित होता है।

भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकता के प्रति सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। समय की मांग है कि खेती को लेकर वैचारिक शिथिलता और संस्थागत निष्क्रियता को खत्म किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति

अनुसंधान संस्थान ने बीते दिनों में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों की कमी की ओर बढ़ते विश्व में खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया था। तकनीक के बढ़ते प्रयोग ने किसानों के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावनाएँ पैदा की थी।

यह दशक भारत में तकनीकी क्रांति का नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर है। जब ग्रामीण भारत संचार और सूचना–तंत्र के वैश्विक पटल पर अपना पदार्पण कर रहा है। सत्तर करोड़ ग्रामीण आबादी को सम्मिलित कर, भारत का डिजिटल इप्रिंट, किसान और कृषि के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने जा रहा है। बदलते भारत में कृषि आधुनिक मशीनरी और जैवप्रौद्योगिकी के नए प्रयोगों को आत्मसात करने को अग्रसर है।

- डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय भाषा से संचालित होने वाले तथा कम लागत में विशेष रूप से तैयार किये गए मोबाइल फोन ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल–व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं।
- सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक अबाधित बिजली–आपूर्ति, सस्ती इंटरनेट–कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाली बैकिंग सेवाओं की व्यवस्था करने से ग्रामीण भारत न केवल डिजिटल रूप से साक्षार होगा, बल्कि उसका सामाजिक–आर्थिक उत्थान भी संभव हो सकेगा।
- संस्थागत ऋण की व्यवस्था से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को अनौपचारिक से औपचारिक व्यवस्था में परिवर्तित करने में सहायता मिल सकती है।
- डिजिटल भुगतान आदि के समय होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिये सरकार को साइबर सुरक्षा मजबूत करनी चाहिये।
- व्यापारिक गतिविधियों के दौरान डिजिटल भुगतान के लिये दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षारता अभियान के तहत 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बेहतर परिणाम की प्राप्ति के लिये इस योजना में और अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है और लगभग पूरी ग्रामीण आबादी तक डिजिटलीकरण की पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।[6]

डिजिटलकरण उत्पादन और वितरण प्रक्रिया में सुधार लाता है और आर्थिक–विकास को गुणात्मक रूप से प्रभावित करता है। लेकिन डिजिटल इंडिया जैसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य वाले अभियान तभी सफल होंगे, जब भारत के डिजिटल पिरामिड के सबसे निचले स्तर अर्थात् ग्रामीण भारत का आर्थिक रूप से भी इतना सक्षम होना जरूरी है कि डिजिटलीकरण के लिये आवश्यक उपकरणों तक उसकी आसान पहुँच बनी रहे।

ग्रामीण और शहरी भारत के बीच के डिजिटल डिवाइड को कम करके ही देश में शत–प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. श्रीवास्तव, ए0आर0एन0, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0 25
2. कुरूक्षेत्र, पत्रिका, भारत सरकार, अगस्त 2017, पृ0 15
3. अहूजा राम, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, पृ0 53
4. योजना पत्रिका, भारत सरकार, जनवरी 2017, पृ0 18
5. ओझा, एस0के0, जनसंख्या एवं नगरीकरण, बौद्धिक प्रकाशन, पृ0 31
6. www.wikipedia.com